

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय
लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2707
16.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

बीएचईएल, त्रिची में विविधीकरण संबंधी कार्यकलाप और इलेक्ट्रिक बस निर्माण का पुनरुद्धार

2707 श्री दुरई वाइको:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मौजूदा मशीनरी और बुनियादी ढांचे के साथ, बीएचईएल, त्रिची पारंपरिक बॉयलर और बिजली क्षेत्र के घटकों के अतिरिक्त वैकल्पिक उत्पादन धाराओं में विविधता लाने में सक्षम है;

(ख) यदि हां, तो उपलब्ध बुनियादी ढांचे और कार्यबल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए बीएचईएल, त्रिची में वर्तमान में किए जा रहे वैकल्पिक उत्पादन कार्यों और परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बीएचईएल की अन्य इकाइयों के समन्वय से बीएचईएल, त्रिची में इलेक्ट्रिक बसों और संबंधित घटकों के उत्पादन की पहल की है या समर्थन दिया है;

(घ) यदि हाँ, तो इलेक्ट्रिक बस उत्पादन की वर्तमान में क्या स्थिति है और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ग्रीन ट्रांसपोर्ट पर देश भर में बढ़ते ध्यान के बावजूद, ऐसी विनिर्माण गतिविधियों को जारी क्यों नहीं रखा गया है या बढ़ाया क्यों नहीं गया है; और

(ड) क्या सरकार का मेक इन इंडिया और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के हिस्से के रूप में बीएचईएल, त्रिची में इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी विनिर्माण गतिविधियों को पुनर्जीवित या विस्तारित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): उपलब्ध सुविधाओं और कार्यबल का अधिकतम उपयोग करने के लिए, बीएचईएल त्रिची ने अपने व्यवसाय का विस्तार तेल और गैस, रक्षा आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में भी किया है। बॉयलर निर्माण के अलावा, बीएचईएल त्रिची रणनीतिक उपकरण भी बनाती है, जिसमें युद्धक टैंकों और अन्य रक्षा संबंधी घटकों के लिए थर्मो-प्रेस्ट प्लेटें और ओएनजीसी के लिए तेल क्षेत्र के उपकरण शामिल हैं।

(ग) और (घ): जी नहीं। हालांकि, बीएचईएल त्रिची ने अपनी पहल पर वर्ष 2018 में 12 मीटर ई-बसों के निर्माण की परियोजना शुरू की। इसे बंद कर दिया गया क्योंकि बीएचईएल का व्यावसायिक मॉडल मुख्य रूप से उत्पाद निर्माण/मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम)/परियोजना निष्पादन पर केंद्रित है, जो ई-मोबिलिटी के सेवा-उन्मुख मॉडल के साथ तालमेल नहीं बिठाता था।

(ड): वर्तमान में, भारी उद्योग मंत्रालय के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।